



दक्षिण भारत राष्ट्रमत

தக்ஷிண் பாரத் ராஷ்ட்ரமத் | தினகரி ஹிந்தி நாளிதழ் | चेन्नई और बंगलूरु से एक साथ प्रकाशित



5 असम में कुछ 'अजीब' लोग आ रहे हैं, सीमा लांघी' तो होंगे गिरफ्तार : हिमंत बिश्व शर्मा

6 साझेदारी और बराबरी से ही टिकेगा आधुनिक विवाह

7 प्रभास बहुत बड़े स्टार, फिर भी पहले सी मासूमियत बरकरार : श्रीदेवी विजयकुमार

फर्स्ट टेक

प्रधानमंत्री मोदी एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए चीन जाएंगे

नई दिल्ली/भाषा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित डोभाल ने मंगलवार को चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ वार्ता के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के आगामी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन जाएंगे। सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता के नए संस्करण में टेलीविजन पर दिए अपने संबोधन में डोभाल ने भारत-चीन संबंधों में "नई ऊर्जा और गति" के साथ-साथ सीमा पर शांति के महत्व को भी रेखांकित किया। एनएसए ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए चीन का दौरा करेंगे और इसलिए आज की वार्ता का विशेष महत्व है। यह 31 अगस्त और एक सितंबर को शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मोदी की चीनी शहर तियानजिन यात्रा की पहली आधिकारिक पुष्टि है।

तीन दिन की यात्रा पर रूस रवाना होंगे जयशंकर

नई दिल्ली/भाषा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज रूस की तीन दिन की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होंगे जहां वह रूस के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता के अलावा भारत-रूस व्यापार मंच की बैठक में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि डॉ. जयशंकर कि यह यात्रा रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान वह बुधवार को निर्धारित भारत-रूस अंतर-सरकारी व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग आयोग (आईआरआईजीसी-टीईसी) के 26वें सत्र की सह-अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्री मॉस्को में भारत-रूस व्यापार मंच की बैठक को भी संबोधित करेंगे।

ताइवान पर भारत के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है : सरकारी सूत्र

नई दिल्ली/भाषा। ताइवान पर भारत के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है और नई दिल्ली के ताइवान के साथ आर्थिक, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित रिश्ते हैं। सरकारी सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। यह स्पष्टीकरण ऐसे वक्त में आया है जब चीनी मीडिया में खबरें हैं कि विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोमवार को अपने चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात के दौरान यह पुनः पुष्टि की कि नई दिल्ली, ताइवान को चीन का हिस्सा मानता है। ऐसी जानकारी है कि जयशंकर ने वांग के साथ वार्ता में ताइवान मुद्दे पर कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं की। सूत्रों ने कहा, ताइवान पर हमारे रुख में कोई बदलाव नहीं है।

भारत और चीन के संबंध वैश्विक शांति व समृद्धि में योगदान देंगे : मोदी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com



नई दिल्ली/भाषा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात के दौरान चीन के साथ सीमा पर शांति और सौहार्द बनाए रखने के महत्व को रेखांकित किया तथा सीमा संबंधी मुद्दों के निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई।

मोदी ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, पूर्वानुमानित और रचनात्मक संबंध क्षेत्रीय और वैश्विक शांति में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह चीन के शहर तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के आगामी शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मिलने के लिए उत्सुक हैं।

सोमवार को दो दिवसीय

यात्रा पर दिल्ली पहुंचे वांग ने मोदी को शी की ओर से एक संदेश और एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए निमंत्रण सौंपा। भारत और चीन द्वारा पूर्वी लद्दाख में गतिरोध समाप्त करने पर सहमति जताए जाने के दो दिन बाद, मोदी और शी ने पिछले साल अक्टूबर में रूसी शहर कज़ान में मुलाकात की थी। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने तथा सीमा विवाद को सुलझाने के लिए कई तंत्रों को बहाल करने पर सहमति व्यक्त की थी। वांग की

चीन उर्वरकों, दुर्लभ मृदा खनिजों की आपूर्ति भारत को बहाल करने के लिए सहमत

नई दिल्ली/भाषा। चीन ने भारत को उर्वरकों और दुर्लभ मृदा खनिजों की आपूर्ति से जुड़े प्रतिबंधों में ढील देने पर सहमति जताई है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर को उनके चीनी समकक्ष वांग यी ने इस मुद्दे पर हुई प्रगति से अवगत कराया। भारत की दो दिवसीय यात्रा पर आए वांग ने सोमवार को जयशंकर के साथ अपनी वार्ता के दौरान यह आश्वासन दिया। सूत्रों ने बताया कि चीन ने भारत की तीन प्रमुख घिंताओं का समाधान करने का वादा किया है।



हवाई अड्डों की तर्ज पर

अब रेल यात्री भी तय वजन तक ही सामान ले जा सकेंगे

प्रयागराज (उप्र)/भाषा। रेल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अवांछित वस्तुओं जैसे मादक पदार्थ आदि के परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल ने यात्रियों के लिए निर्धारित वजन से अधिक के सामान पर शुल्क लगाने की तैयारी की है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक हिमांशु शुक्ला ने 'पीटीआई भाषा' से कहा कि रेल यात्रा के दौरान बिना बुकिंग वाला सामान बहुत अधिक संख्या में देखने को मिलता है और सामान में मादक पदार्थ जैसी वस्तुएं पकड़ी जाती हैं। उन्होंने बताया कि हवाई अड्डों की तरह रेलवे स्टेशनों पर भी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर प्रवेश और निकासी द्वार पर सामान की जांच करने वाली मशीन लगाने और सभी तरह के सामान की जांच करने की तैयारी की जा रही है। शुक्ला ने बताया कि हवाईअड्डों की तर्ज पर सामान में टैग लगाया जाएगा और यात्रियों से निर्धारित वजन से अधिक के सामान की बुकिंग पार्सल की दर से कराने को कहा जाएगा। मसलन, 'एसी फर्स्ट क्लास' में 70 किलोग्राम तक के वजन का सामान ले जाने की अनुमति होगी और इससे अधिक के सामान को पार्सल माना जाएगा और शुल्क वसूला जाएगा।

दुनिया की मुख्य चुनौतियों के समाधान में भारत अनिवार्य हिस्सा : राष्ट्रपति

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को कहा कि भारत दुनिया की मुख्य चुनौतियों के समाधान का एक अनिवार्य हिस्सा है-चाहे वह 'ग्लोबल नॉर्थ' और 'ग्लोबल साउथ' के बीच असमानता से उत्पन्न मुद्दों हैं, सीमा पार आतंकवाद के खतरे हों या जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां हों। 'ग्लोबल नॉर्थ' शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर आर्थिक रूप से विकसित और औद्योगिक देशों के लिए किया जाता है, वहीं 'ग्लोबल साउथ' का इस्तेमाल आर्थिक रूप से कम संपन्न देशों के संदर्भ में होता है। राष्ट्रपति भवन में भारतीय विदेश सेवा (2024 बैच) के प्रशिक्षु अधिकारियों के एक समूह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने उनसे वसुधैव कुटुम्बक की भावना को अपनाते हुए राष्ट्रहित सर्वोपरि को ध्यान में रखने को कहा।

मुर्मू ने कहा कि उनके आसपास की दुनिया भू-राजनैतिक बदलावों, डिजिटल



क्रांति, जलवायु परिवर्तन और बहुपक्षवाद के संदर्भ में तेजी से बदलाव देख रही है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षु अधिकारी 'अमृत काल' में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए हैं-एक ऐसा समय जब भारत वैश्विक मंच पर एक अग्रणी शक्ति के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है। राष्ट्रपति ने कहा, आज भारत विश्व की मुख्य चुनौतियों के समाधान का एक अनिवार्य हिस्सा है-चाहे वह 'ग्लोबल नॉर्थ' और 'ग्लोबल साउथ' के बीच असमानता से उत्पन्न मुद्दे हों, सीमा पार आतंकवाद के खतरे हों या जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां हों। उन्होंने कहा, हमारी आवाज का

महत्व है। हमारे राजनयिकों के रूप में, आप भारत का पहला चेहरा होंगे जिसे दुनिया आपके शब्दों में, आपके कार्यों में और आपके मूल्यों में देखेगी। राष्ट्रपति ने कहा, हम वसुधैव कुटुम्बक की भावना को अपनाते हैं, लेकिन कृपया यह ध्यान रखें - राष्ट्रहित सर्वोपरि हो। मुर्मू ने कहा कि देश के कूटनीतिक प्रयास हमारी घरेलू जरूरतों और 2047 तक विकसित भारत बनने के हमारे उद्देश्य के साथ निकटता से जुड़े होने चाहिए। राष्ट्रपति ने उनसे हमारे सम्यक्तागत ज्ञान-शांति, बहुलवाद, अहिंसा और संवाद के मूल्यों को अपने साथ लेकर चलने का आग्रह किया।

कर्नाटक विस ने दी 'गिग' कर्मियों के कल्याण संबंधी विधेयक को मंजूरी

बेंगलूरु/भाषा। कर्नाटक विधानसभा ने 'गिग' श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने, उनकी सामाजिक, व्यावसायिक और स्वास्थ्य सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके 'एग्रीगेटर' को देने संबंधी एक विधेयक को मंगलवार को मंजूरी दे दी। कर्नाटक प्लेटफॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स (सामाजिक सुरक्षा और कल्याण) विधेयक, 2025, विभिन्न श्रेणियों के समन्वयकों या प्लेटफॉर्म के लिए प्रत्येक लेनदेन के दौरान कार्यकर्ता को भुगतान के 1 से 5 प्रतिशत का कल्याण शुल्क प्रस्तावित करता है। विधेयक में विवाद समाधान तंत्र उपलब्ध करने के लिए स्वचालित निगरानी और निर्णय लेने की प्रणालियों में पारदर्शिता, गिग श्रमिक कल्याण बोर्ड की स्थापना, मंच आधारित गिग श्रमिकों के लिए कल्याण निधि का सृजन तथा मंच आधारित गिग श्रमिकों को बोर्ड के साथ पंजीकृत होना आवश्यक करने का प्रावधान है। इसके अलावा विधेयक में एग्रीगेटर या मंच का पंजीकरण करने और मंच आधारित गिग श्रमिकों को आय सुरक्षा और उचित कार्य स्थितियों के संबंध में प्रावधान है।



भारत-चीन संबंध अब और मजबूत हुए हैं : डोभाल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने मंगलवार को कहा कि पिछले नौ महीनों में भारत-चीन संबंधों में सुधार आया है क्योंकि सीमा पर शांति बनी हुई है। उन्होंने चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ सीमा पर तनाव कम करने और संबंधित मुद्दों पर बातचीत की।

डोभाल और वांग ने विशेष प्रतिनिधि तंत्र के ढांचे के तहत 24वें दौर की वार्ता की, जिसके एक दिन पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने चीनी समकक्ष से मुलाकात की थी।



पूर्व न्यायाधीश

सुदर्शन रेड्डी होंगे विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन ने उद्यम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना संयुक्त उम्मीदवार घोषित किया है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को अपने सरकारी आवास पर आयोजित संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्षी दलों

के उम्मीदवार के रूप में रेड्डी के नाम का एलान किया। इस दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार, तुणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन, द्रविड मुनेत्र कषगम की कनिमोडी तथा तिरुचि शिवा, शिव सेना (उद्भव) के अरविंद सावंत तथा संजय राजत, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पी संदोष कुमार, कांग्रेस के के सुरेश, के सी वेणुगोपाल तथा प्रमोद तिवारी, आरएसपी के एन के प्रेमचंद्रन, आईयूपएमएल के ईटी मोहम्मद बशीर, समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव सहित कई नेता मौजूद थे।

19-08-2025 20-08-2025
सूर्योदय 6:27 बजे सूर्यास्त 5:57 बजे

BSE 81,644.39 (+370.64)
NSE 24,980.65 (+103.70)

सोना 10,418 रु. (24 कैरेट) प्रति ग्राम
चांदी 127,000 रु. प्रति किलो

मिशन मंडेला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com



केलाशा मण्डेला, मो. 9828233434

कटघरे में कानून

फौसी या उम्र कैद से क्या, अपराधी सचमुच डर लेगा? धाराओं की कारा में क्या, गंदे मनसूबे हर लेगा? जज ही जब खड़े कटघरे में, कानून सख्त क्या कर लेगा? जेबों में बैठ समर्थों की, खुद को ताकों में धर लेगा।।

रिसाव के चलते 'एक्सओम 4' मिशन 'विनाशकारी' होता : इसरो प्रमुख

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

हैदराबाद/भाषा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने मंगलवार को कहा कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने भारत के शुभांशु शुक्ला और तीन अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को आईएसएस ले जाने वाले रॉकेट की मुख्य 'फीड लाइन' में दरार की पहचान की थी जिसके कारण प्रक्षेपण कार्यक्रम में बदलाव किया गया। उन्होंने कहा कि यदि इस समस्या के साथ मिशन जारी रहता तो यह एक "विनाशकारी फिलहाल" साबित होता। उन्होंने बताया कि इस दरार के कारण 'एक्सओम-4' मिशन (एक्स-4) को उसी महीने 11 जून के बजाय 25 जून के लिए स्थगित करना पड़ा था।

नारायणन ने यहां उरमानिया विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा से पहले की घटनाओं का विवरण देते हुए कहा कि अमेरिका के केंनेडी अंतरिक्ष केंद्र



में डेरा डाले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की टीम को 10 जून को रॉकेट में खामी के बारे में पता चला, जिसके बाद भारतीय वैज्ञानिकों ने इस मुद्दे की विस्तृत पड़ताल करने को कहा। अंतरिक्ष विभाग के सचिव नारायणन ने कहा, कुल 14 प्रश्न पूछे गए थे और किसी भी अग्र का संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया, जिसमें यह भी शामिल था कि रिसाव कहां था। इसकी

पहचान नहीं हो पाई। हमने संपूर्ण सुधार की मांग की, क्योंकि हम बहुत स्पष्ट थे। चूंकि मैं 40 वर्षों से उस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि यदि कोई रॉकेट रिसाव के साथ उड़ान भरता है तो क्या कठिनाई होती है।

इसके बाद, भारत सरकार की मांग के आधार पर भारतीय टीम ने एक नोट प्रस्तुत किया और संपूर्ण रिसाव को ठीक कर दिया गया। उन्होंने बताया कि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा निरीक्षण किए जाने और मुख्य फीड लाइन में दरार पाए जाने पर 11 जून को निर्धारित पहला प्रक्षेपण रद्द कर दिया गया। नारायणन ने कहा, अगर रॉकेट (रिसाव के साथ) उड़ान भरता, तो यह एक विनाशकारी विफलता होती।



मणिका विश्वकर्मा बर्नी मिस इंडिया यूनिवर्स

जयपुर/भाषा। राजस्थान के गंगानगर निवासी मणिका विश्वकर्मा ने मिस इंडिया यूनिवर्स 2025 का ताज अपने नाम किया है और वह इस साल के अंत में थाईलैंड में होने वाली 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। विश्वकर्मा (22) ने 18 अगस्त को जयपुर के ज़ी स्टूडियो में आयोजित एक भव्य समारोह में यह खिताब अपने नाम किया। मंगलवार तड़के तक चले इस समारोह में विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिंघा ने ताज पहनाया। उत्तर प्रदेश की 22 वर्षीय तान्या शर्मा प्रथम उपविजेता रहीं और हरियाणा की 19 वर्षीय महक डींगरा द्वितीय उपविजेता रहीं। हरियाणा की 23 वर्षीय अमीठी कौशिक और मणिपुर की 24 वर्षीय सारंगधरम निरुपमा क्रमशः तीसरी और चौथी उपविजेता रहीं।

महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश से 10 लोगों की मौत, अगले 48 घंटे अहम

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में मंगलवार को हुई मूसलाधार बारिश से जुड़ी घटनाओं में 10 लोगों की मौत हो गई वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई लगभग थम सी गई, संपत्तियों और फसलों को नुकसान पहुंचा और सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा।

मुंबई और उसके महानगरीय क्षेत्र में रेल सेवाएं और उड़ानों के प्रभावित होने के अलावा, विदर्भ क्षेत्र के गडचिरोली और मराठवाड़ा क्षेत्र के नांदेड सहित अन्य जिलों में भारी बारिश हुई।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आपदा प्रबंधन विभाग के साथ बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करने के बाद कहा कि अगले 48 घंटे मुंबई, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के लिए महत्वपूर्ण होंगे, जहां 'हाई अलर्ट' घोषित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि महाराष्ट्र के नांदेड जिले में बादल फटने जैसी स्थिति के कारण आई



मोनोरेल ट्रेन दो स्टेशन के बीच फंसी, 200 यात्रियों को निकाला गया

मुंबई/भाषा। मुंबई में भारी बारिश के बीच मंगलवार शाम को मैसूर कॉलोनी और भक्ति पार्क स्टेशन के बीच एक मोनोरेल ट्रेन बिजली परोक्ष तौर पर बिजली आपूर्ति में दिक्कत आने के कारण फंसी गई। बचाव कार्य के दौरान 200 से अधिक यात्रियों को निकल लिया गया। मुंबई के अतिरिक्त नगर आयुक्त अश्विनी जोशी ने बताया कि बिजली आपूर्ति बाधित होने से ट्रेन रुक गई और इसके बाद बचाव कार्य शुरू किया गया। उन्होंने बताया कि मोनोरेल से 200 से अधिक यात्रियों को निकाल लिया गया है और बचाव कार्य जारी है। फंसी ट्रेन से निकाले गए यात्रियों ने बताया कि एलिवेटर ट्रेक पर चलने वाली ट्रेन के अंदर दहशत का माहौल था और कई लोगों ने दम घुटने की शिकायत की क्योंकि वातावरण प्रणाली बंद हो गई थी।

बाद में आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि मुंबई में लगभग 300 मीमी की रिकॉर्ड बारिश हुई। उन्होंने कहा कि भारी बारिश के कारण 12 से 14 लाख एकड़ भूमि में लगी फसलों

को नुकसान हुआ है। फडणवीस ने कहा कि बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है और जल प्रबंधन के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय किया जा रहा है।



‘जीतो’ नॉर्थ द्वारा आयोजित होने वाले ‘जीतो ज़ेवर एक्सपो एवं दि ब्राइडल स्टोरी’ की तैयारियां जोरों पर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। जीतो नॉर्थ द्वारा 5 सितम्बर से आयोजित होने वाले तीन दिवसीय ‘जीतो ज़ेवर एक्सपो एवं दि ब्राइडल स्टोरी’ एक्सपो की तैयारियाँ अपनी चरम सीमा पर हैं। पैलेस ग्राउंड स्थित त्रिपुरावासनी सभागार में 1 लाख वर्ग फीट क्षेत्रफल में इस एक्सपो का आयोजन होने जा रहा है। राजाजीनगर कार्यालय में आयोजित तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक में नॉर्थ के चेयरमैन विमल कटारिया ने एक्सपो की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि यह आयोजन पूरे भारत में अपनी

एक अलग पहचान बनाएगा। उन्होंने बताया कि इस एक्सपो में देशभर के प्रतिष्ठित व्यापारी एवं विशेष अतिथि शामिल होंगे। उन्होंने आगे कहा कि हम मेहमाननवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। प्रतिदिन आने वाले पहले 1000 विजिटर्स के लिए हॉम्पिलो कम्पनी की ओर से विशेष मिफ्ट की व्यवस्था रहेगी। महामंत्री विजय सिंघवी ने कार्य की सुचारु रूप से क्रियान्विति और उसे और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि टीम वर्क और पारदर्शिता ही इस एक्सपो की

सरकार ने 30 सितंबर तक कपास के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति दी

नई दिल्ली/भाषा। सरकार ने कपड़ा क्षेत्र के लिए प्रमुख कच्चे माल की उपलब्धता सुधारने के मकसद से 30 सितंबर तक कच्चे कपास के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति दी है। इस कदम से अमेरिका को फायदा मिलने की उम्मीद है। कपास पर अब तक कृषि अवसरंचना एवं विकास उपकर के साथ 11 प्रतिशत का आयात शुल्क भी लगता रहा है। वित्त मंत्रालय की 18 अगस्त की अधिसूचना के अनुसार, शुल्क छूट 19 अगस्त से प्रभावी होगी और 30 सितंबर तक लागू रहेगी। आयात शुल्क समाप्त करने से कपड़ा क्षेत्र के लिए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी दरों पर कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित होने की उम्मीद है। भारत द्वारा

भारत, अमेरिका वस्तुओं के व्यापार को उदार बनाने पर बातचीत कर रहे हैं : जितिन प्रसाद

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। सरकार ने मंगलवार को संसद में कहा कि भारत और अमेरिका एक बहु-क्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं तथा वार्ता के एक हिस्से के तहत दोनों पक्ष गैर-संवेदनशील कृषि उत्पादों सहित वस्तुओं के व्यापार के उदारीकरण पर चर्चा कर रहे हैं। गैर-संवेदनशील कृषि उत्पादों को आम तौर पर उन उत्पादों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो अक्सर उनके कम आर्थिक या रणनीतिक महत्व के कारण विशेष व्यापार प्रतिबंधों या संरक्षण के अधीन नहीं होते हैं। वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किसानों और कृषि क्षेत्र के हितों और आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए कृषि, कृषि विशेषज्ञों सहित

सभी संबंधित हितधारकों के साथ बातचीत कर रही है। उन्होंने कहा, भारत और अमेरिका एक बहु-क्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के एक हिस्से के रूप में, अन्य बातों के अलावा, दोनों पक्ष गैर-संवेदनशील कृषि उत्पादों सहित वस्तुओं के व्यापार के उदारीकरण पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य व्यापार का विस्तार करना और भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों को प्रगाढ़ करना है। उन्होंने अपने लिखित जवाब में उल्लेख किया कि सरकार देश के राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने और आगे बढ़ाने तथा किसानों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की हिफाजत और

हार के बाद इज्जत बचाने के लिए ‘वोट चोरी’ जैसे आरोप लगाना कांग्रेस की परिपाटी : धामी

जिला पंचायत अध्यक्ष तथा बाजपुर में ब्लॉक प्रमुख के पद पर कांग्रेस की जीत का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां कोई गड़बड़ी नहीं हुई। धामी ने कहा कि पूरे देश में अब इनकी पार्टी (कांग्रेस) की यह आदत बन गई है कि जब भी वे किसी चुनाव में हारते हैं, तो अपनी हार स्वीकार करने के बजाय कभी ईवीएम को दोषी ठहराते हैं, कभी निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाते हैं, कभी प्रशासन या सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं और कभी ‘वोट चोरी’ की बात कहने लगते हैं, ताकि अपनी इज्जत बचाई जा सके। उन्होंने कहा कि जनता भलीभांति जानती है कि कांग्रेस के कालखंडों में किस प्रकार से वोटों की चोरी हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा, जिस नैनीताल की बात हो रही है, वहां जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर हमारी पार्टी की प्रत्याशी दीपा दर्मवाल निर्वाचित हुई हैं और वहीं उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस निर्वाचित हुई है। अगर यह निष्पक्ष चुनाव नहीं होता तो दोनों ही पद भाजपा को मिलते। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनावों के अलावा लोकसभा, विधानसभा, नगर निकाय आदि सभी चुनावों में भाजपा को मिली भारी जीत के कारण कांग्रेस में हताशा और निराश भर गई है।

यहां संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में निष्पक्ष पंचायत चुनाव हुए हैं और एकाध जगह कानून-व्यवस्था की जो स्थिति खराब हुई है, उसे लेकर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां कांग्रेस जीतती है, वहां कोई गड़बड़ी नहीं होती। धामी ने इस संबंध में देहरादून

संसद ने दी खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025 को मंजूरी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। संसद ने मंगलवार को देश के खनन क्षेत्र के विनियमन और खनिजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रावधानों वाले ‘खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025’ को पारित कर दिया। राज्यसभा में इस विधेयक पर चर्चा एवं खान और खनन मंत्री जी किशन रेड्डी के जवाब के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। राज्यसभा में इस विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस एवं कई अन्य दलों के सदस्य मौजूद नहीं थे। विपक्षी सदस्यों ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर सदन से बहिर्गमन किया था। रेड्डी ने

विधेयक पर हुई चर्चा के जवाब में कहा कि इस विधेयक के माध्यम से खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में छह संशोधन संसद के सामने लाए गए हैं जो खान क्षेत्र के हित में हैं। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में अति महत्वपूर्ण (क्रिटिकल) खनिजों की बेहद मांग है और सोलर पैनल से लेकर विंड टर्बिन तक, बिजली से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक, सेलफोन से लेकर विमानों तक, खेती से लेकर रक्षा और अंतरिक्ष तक हर क्षेत्र में इनकी जरूरत है। खान मंत्री ने कहा कि लिथियम जैसे अति महत्वपूर्ण खनिज की आपूर्ति सुगम बनाने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि देश में खनिज उत्पादन को बढ़ाने में इस विधेयक के प्रावधानों से मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने 24 ‘अत्यंत महत्वपूर्ण खनिजों’ को

भगवान वेंकटेश्वर स्वामी को 121 किलो सोना दान करेगा भक्त : चंद्रबाबू नायडू

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

अमरावती/भाषा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को कहा कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के एक भक्त ने अपनी उद्यमशील सफलता के लिए कृच्छ्रता स्वरूप भगवान को 121 किलोग्राम सोना दान करने का फैसला किया है। इस सोने की कीमत लगभग 140 करोड़ रुपए है। नायडू ने कहा कि वह (भक्त) एक कंपनी स्थापित करना चाहता था और इसमें उसे सफलता हासिल हुई। मंगलागिरी में ‘गरीबी उन्मूलन’ कार्यक्रम पी4 को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, उस भक्त ने ईश्वर को कुछ लौटाने का फैसला किया है। अब वह वेंकटेश्वर स्वामी को 121 किलोग्राम सोना दे रहा है। नायडू ने कहा कि उक्त भक्त गुमनाम रहना चाहता है। उन्होंने बताया कि भक्त ने अपनी कंपनी के

60 प्रतिशत शेयर बेचकर 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 6,000 करोड़ रुपए से 7,000 करोड़ रुपए अर्जित किए और उनका मानना है कि यह समृद्धि उन्हें श्री वेंकटेश्वर स्वामी की कृपा से प्राप्त हुई, इसलिए उन्होंने भगवान को दान करने का निर्णय लिया। तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के प्रमुख ने बताया कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति को प्रतिदिन लगभग 120 किलो सोने के आभूषणों से सजाया जाता है। उन्होंने बताया कि जब उन्हें इस बात का पता चला, तो एक भक्त ने आगे आकर 121 किलो सोना दान करने के लिए कहा।

जम्मू-कश्मीर : कैलाश कुंड यात्रा को प्रतीकात्मक अनुष्ठानों तक सीमित किया

जम्मू/भाषा। जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में बुधवार से शुरू होने वाली तीन दिवसीय कैलाश कुंड यात्रा को हाल ही में बादल फटने की घटनाओं और खराब मौसम के पूर्वानुमान के कारण इस साल प्रतीकात्मक अनुष्ठानों तक सीमित कर दिया गया है। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। डोडा के उपायुक्त हरविंदर सिंह ने इच्छुक तीर्थयात्रियों से अनुरोध किया कि वे वार्षिक यात्रा में शामिल होने का कोई प्रयास न करें। इस यात्रा में आमतौर पर केंद्र शासित प्रदेश के भीतर और बाहर से हजारों श्रद्धालु आते हैं। करीब 14,700 फुट ऊंचे कैलाश कुंड की तीर्थयात्रा सबसे कठिन तीर्थयात्राओं में से एक मानी जाती है, क्योंकि तीर्थयात्रियों को इस ऊंचे मंदिर में दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत श्रृंखला की 18 किलोमीटर की खड़ी बढ़ाई चढ़नी पड़ती है।

अंतरिक्ष में 75 टन भार ले जाने के लिए 40 मंजिला ऊंचे रॉकेट पर काम कर रहा है इसरो : नारायणन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

हैदराबाद/भाषा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) प्रमुख वी. नारायणन ने मंगलवार को कहा कि अंतरिक्ष एजेंसी एक ऐसे रॉकेट पर काम कर रही है, जिसकी ऊंचाई 40 मंजिला इमारत जितनी होगी और जो 75,000 किलोग्राम भार वाले ‘पेलोड’ को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने में सक्षम होगा। नारायणन ने यहां उस्मानिया विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कहा कि इस वर्ष इसरो ने कई महत्वपूर्ण मिशन तय किए हैं, जिनमें ‘नेविगेशन विद इंडिया कॉन्टेलेशन सिस्टम’

था। आज हम 75,000 किलोग्राम भार ले जाने वाले रॉकेट की कल्पना कर रहे हैं, जिसकी ऊंचाई 40 मंजिला इमारत जितनी होगी। उन्होंने बताया कि इसरो ने इस वर्ष ‘टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन सैटेलाइट’ (टीडीएस) और जीसेट-7आर (भारतीय सेना के लिए संचार उपग्रह) सहित कई उपग्रहों का प्रक्षेपण करने की योजना बनायी है। उन्होंने कहा कि जीसेट-7आर विशेष रूप से भारतीय नौसेना के लिए डिजाइन किया गया है और यह जीसेट-7 (सर्किटिंग) उपग्रह की जगह लेगा। नारायणन ने कहा कि फिलहाल भारत के 55 उपग्रह

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

की भावना के चलते सभी पक्षों को विश्वास में लिया गया है जिसका परिणाम इस क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि ‘विकसित भारत’ का लक्ष्य पूरा करने के संकल्प और विश्व में अहम भूमिका निभाने के उद्देश्य के साथ पूरी ईमानदारी के साथ काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा “2014 से पहले खनन क्षेत्र में भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद था और लोगों का भरोसा खत्म हो चुका था। तब नीति पंगुता का दौर था। लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। राजग सरकार के अथक प्रयासों का नतीजा है कि आज भारत दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश बन चुका है और देश में कोयले का आयात घटा है। रेड्डी ने कहा कि आज स्थिति यह है कि कोयला ब्लॉक का आवंटन निविदा के

माध्यम से किया जाता है और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि आज देश में बिजली संकट बिल्कुल नहीं है क्योंकि बिजली के लिए जितने कोयले की जरूरत है, उतना कोयला देने के लिए सरकार तैयार है। उन्होंने कहा कि खनिज राष्ट्र की संपदा है और इसका उपयोग राष्ट्र के विकास के लिए होना चाहिए। रेड्डी ने कहा कि नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग से खनिजों के उत्पादन में वृद्धि हुई है और उनका राजस्व भी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि रॉयल्टी व्यवस्था के तहत पूरी राशि राज्यों को दी जाती है। रेड्डी के जवाब के बाद विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इसके बाद चार बज कर 45 मिनट पर उच्च सदन की बैठक को बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

डाक विभाग ने 5,800 करोड़ रुपए की उन्नत डाक प्रौद्योगिकी देशभर में लागू की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। डाक विभाग ने 5,800 करोड़ रुपए की लागत वाली ‘उन्नत डाक प्रौद्योगिकी’ (एपीटी) पूरे देश में लागू कर दी है जिससे विभाग को एक विश्वस्तरीय सार्वजनिक लॉजिस्टिक संगठन के रूप में बदला जा सकेगा। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इस उन्नत मंच के जरिये डाकघर अब किसी भी बंके के ग्राहकों से यूपीआई भुगतान स्वीकार कर सकेंगे। अभी तक तकनीकी कारणों से यूपीआई भुगतान डाकघरों में केवल इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक खातों तक ही सीमित था। एपीटी की मदद से डाक विभाग को विश्वस्तरीय संगठन बनाने के लिए मोबाइल आधारित सेवाएं तथा वास्तविक समय में निर्णय लेने की सुविधा का

इस्तेमाल किया जाएगा। सिंधिया ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा, डाक विभाग की तरफ से पूरे देश में उन्नत डाक प्रौद्योगिकी (एपीटी) लागू किए जाने की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। यह भारत की डिजिटल यात्रा में ऐतिहासिक कदम है। आईटी 2.0 के तहत 5,800 करोड़ रुपए के निवेश से समर्थित एपीटी डाक विभाग को विश्वस्तरीय सार्वजनिक लॉजिस्टिक संगठन में बदल देगा। सिंधिया ने कहा कि

‘नांदेड़ में बाढ़ से आठ व्यक्तियों की मौत, मुंबई में रिकॉर्ड 300 मिलीमीटर बारिश’

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में बादल फटने जैसी स्थिति के कारण आठ लोगों की मौत हो गई जबकि मुंबई में करीब 300 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। शहर की जीवनरेखा कही जाने वाली उमनगरीय ट्रेन या तो धीमी हो गई हैं या देरी से चल रही हैं। मीठी नदी (मुंबई में) खतरे के निशान तक पहुंच गई है और 400 से 500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्थिति पर नजर रख हुए हैं। शिंदे लगातार दूसरे सप्ताह केबिनेट बैठक में शामिल नहीं हुए।फण्णवीस ने कहा कि प्रशासन ने शैक्षणिक संस्थानों

और कार्यालयों में छुट्टी की घोषणा की है और निजी कार्यालयों से कहा है कि जहां तक संभव हो, घर से काम करने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा, स्थिति अब नियंत्रण में है। शाम को उच्च ज्वार आने की संभावना है और हम स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल अलर्ट पर हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बांधों से पानी के प्रबंधन के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय किया जा रहा है। उन्होंने कहा, अनियंत्रित जलग्रहण क्षेत्र चिंता का विषय हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कलेक्टर को एनडीआरएफ नियमों के अनुसार, मवेशियों की क्षति, मकानों की क्षति और जानमाल के नुकसान के लिए प्रभावित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देने के संबंध में निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है।

अंतरिक्ष में 75 टन भार ले जाने के लिए 40 मंजिला ऊंचे रॉकेट पर काम कर रहा है इसरो : नारायणन

अंतरिक्ष में सक्रिय हैं और आने वाले तीन से चार वर्षों में यह संख्या तीन गुना बढ़ जाएगी। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक की सफल यात्रा और वापसी से पहले की घटनाओं का क्रम बताते हुए उन्होंने कहा कि मूल परियोजना 11 जून के लिए निर्धारित थी, हालांकि, एक दिन पहले उनके नेतृत्व वाली टीम द्वारा रॉकेट में रिसाव की पहचान करने के बाद इसे 25 जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया। उन्होंने कहा, उसके साथ अगर रॉकेट उड़ान भर लेता, तो वह एक भयावह विफलता होती। भारतीयों के आग्रह पर, भारतीय शिक्षा प्रणाली और इसरो के प्रशिक्षण के आधार पर, रॉकेट को सही किया गया।

“भारत” ब्रांड के तहत अप्रैल 2025 से दालों की खुदरा बिक्री बंद

नई दिल्ली/भाषा। सरकार ने मंगलवार को बताया कि 2023-24 और 2024-25 में “भारत” ब्रांड के तहत चना दाल, मूंग दाल और मसूर दाल खुदरा स्तर पर उपलब्ध कराई गई थी लेकिन अप्रैल 2025 से दालों की खुदरा बिक्री बंद कर दी गई, क्योंकि दालों के दाम स्थिर हो गए हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री निजुबेन जयंतीभाई बाम्बनिया ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह भी बताया कि “भारत आटा” और “भारत चावल” की आपूर्ति आगामी वर्ष में भी जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि “भारत आटा” छह नवम्बर 2023 और “भारत चावल” छह फरवरी 2024 को आम उपभोक्ताओं को सब्सिडी दर पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किए गए थे। यह वितरण खुले बाजार बिक्री योजना (घरेलू) यानी ओएमएसएस (डी) के तहत किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि ओएमएसएस (डी) की 2024-25 की नीति नौ जुलाई 2024 को जारी की गई थी, जिसके तहत इन उत्पादों की बिक्री केंद्रीय सहकारी संस्थाओं के माध्यम से 30 जून 2025 तक हुई। उन्होंने बताया कि अब 2025-26 के लिए नई नीति 10 जुलाई 2025 को अधिसूचित की गई है, जिसके तहत “एनएफआईडी, एनसीसीएफ” और केंद्रीय भंडार जैसे संस्थाओं को गेहूं और चावल की आपूर्ति जारी रहेगी, ताकि “भारत” ब्रांड के तहत खाद्यान्न वितरण सुचारु रूप से हो सके। बाम्बनिया ने बताया कि 2023-24 और 2024-25 में “भारत” ब्रांड के तहत चना दाल, मूंग दाल और मसूर दाल भी खुदरा स्तर पर उपलब्ध कराई गई थी।

सुविचार

सब्र एक ऐसी सवारी है,
जो अपने पे सवार को
कमी गिरने नहीं देती।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

ऑनलाइन गेमिंग : मनोरंजन या बर्बादी ?

देशवासियों द्वारा ऑनलाइन गेम्स पर सूपीआई के जरिए खर्च की गई राशि से संबंधित आंकड़े हैरान करने वाले हैं। लोगों ने चार महीनों में लगभग 41,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इस देश में लाखों लोग मूलभूत जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके पास इलाज के लिए रुपए नहीं हैं। युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। कितने ही बच्चे कुपोषण से ग्रस्त हैं। क्या ऐसे हालात में ऑनलाइन गेम्स पर इतनी भारी-भरकम राशि खर्च कर देना अवलमबी है? डिजिटल पेमेंट एक ऐसी सुविधा है, जिसने कई काम बहुत आसान कर दिए हैं। इसका इस्तेमाल व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की उन्नति के लिए होना चाहिए। जो लोग तुरंत मालामाल होने के लिए ऑनलाइन गेम्स, जुआ, सट्टा आदि में धन लगाते हैं, वे अपने लिए समस्याएं मोल लेते हैं। आज सोशल मीडिया पर हजारों लोग आपबीती बताते मिल जाएंगे, जिन्होंने इस उम्मीद के साथ रुपए लगाए थे कि कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन देखते ही देखते वे लाखों रुपए गंवा बैठे। यह एक ऐसा नशा है, जो व्यक्ति को पूरी तरह गिरफ्त में ले लेता है। उसे अपने हितैषियों की बातें बुरी लगती हैं। वह सोचता है कि एक दांव की ही तो बात है, उसके बाद मैं मालामाल हो जाऊंगा! आज तक कितने लोग इन ऐप्स के जरिए मालामाल हुए हैं? अगर लाखों-करोड़ों लोगों में से दो-चार लोगों को कुछ हजार रुपए मिल भी गए तो इसमें फायदा किसका है? अगर इन ऐप्स को संचालित करने वाली कंपनियां अपने यूजर्स को रुपए बांटने लग जाएंगी तो खुद क्या कमाएंगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं, जिनके बारे में युवाओं को जरूर सोचना चाहिए।

ऑनलाइन गेम्स, जुआ, सट्टा वाले ऐप्स के जाल में फंसकर कई परिवार बर्बाद हो चुके हैं। हाल में व्हालियर में एक किशोर ने ऑनलाइन गेम में 35,000 रुपए हारने के बाद ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली थी। उसे ऑनलाइन गेम की लत लग चुकी थी। इसी साल जून में राजस्थान के कोटा में एक दंपति ने ऑनलाइन सट्टेबाजी में 5 लाख रुपए का कर्ज होने की वजह से आत्महत्या कर ली थी। परिवार का मुखिया स्मार्टफोन के जरिए सट्टा लगाने का शौकीन था। मध्य प्रदेश में एक पखवाड़े में तीन ऐसे मामले काफी चर्चा में रहे, जिन्होंने ऑनलाइन गेम के दुष्प्रभावों को उजागर किया था। उनमें तीन लोगों ने रुपए गंवाने के कारण आत्महत्या कर ली थी। सितंबर 2024 में सोशल मीडिया पर एक उद्यमी के मामले ने सबका ध्यान आकर्षित किया था। उसका व्यवसाय काफी अच्छा चल रहा था। एक दिन उसे किसी ऑनलाइन सट्टा ऐप के बारे में पता चला और वह दांव लगाने लगा। उसे शुरुआत में कुछ लाभ हुआ, लेकिन जल्द ही दांव हारने लगा। उसने मालामाल होने के लालच में 60 लाख रुपए गंवा दिए थे। पहले, उसका परिवार काफी खुशहाल था। सट्टा ऐप ने सबकुछ बर्बाद कर दिया। वह उस घड़ी को कोस रहा है, जब उसने अपने मोबाइल फोन में ऐप डाउनलोड किया था। कई छात्र ऐसे हैं, जिन्होंने अपनी कॉलेज फीस किसी गेमिंग ऐप पर लगा दी और नुकसान होने के कारण गलत कदम उठा लिया। उसका व्यवसाय भी आईआईटी के एक प्रतिभाशाली छात्र ने आत्महत्या कर ली थी। बाद में पता चला कि उसने अपनी फीस ऑनलाइन गेम में लगा दी थी, जहां उसे भारी नुकसान हुआ था। अगर वह ऐसे किसी ऐप के चक्कर में न पड़ता और पढ़ाई पर ध्यान देता तो भविष्य में एक अच्छा इंजीनियर बनता। ऐसे अनगिनत मामले हैं, जो बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मोटी कमाई, मनोरंजन या किसी और मकसद के साथ इन ऐप्स का इस्तेमाल शुरू करता है तो उसे आखिर में नुकसान ही होता है। केंद्र सरकार समय-समय पर ऐसे ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई जरूर करती है, लेकिन सबसे प्रभावी कार्रवाई जनता कर सकती है। इस कार्रवाई का तरीका है- जब भी ऐसा कोई ऐप कमाई का लालच दे, तो अपने मन पर नियंत्रण रखें। अपने फोन में ऐसे ऐप को जगह ही न दें।

ट्वीटर टॉक



डॉ. प्रियंका सोरभ

मोबाइल : 7015375570

आधुनिक जीवनशैली ने जहाँ रिश्तों में नए अवसर खोले हैं, वहीं कई नई चुनौतियाँ भी खड़ी कर दी हैं। शिक्षा, रोजगार और तकनीक ने महिलाओं को पहले से अधिक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाया है। आज की महिला घर के दायरे से निकलकर नौकरी, व्यवसाय और प्रशासनिक जिम्मेदारियों तक सक्रिय रूप से पहुँच रही है। लेकिन विडंबना यह है कि घर की दहलीज के भीतर उसकी स्थिति उतनी नहीं बदली जितनी बदलनी चाहिए थी। अधिकांश परिवारों में अभी भी घरेलू कार्यों की जिम्मेदारी लगभग पूरी तरह से महिलाओं पर ही डाल दी जाती है। इस समस्या का एक मन और चिंताजनक रूप सामने आया है – पति द्वारा घरेलू कामों में जानबूझकर अयोग्यता दिखाना। इसे पश्चिमी समाज में 'वेपनाइज्ड इनकपिटेंस' कहा जाता है, जिसका सीधा अर्थ है कि पति जानबूझकर घरेलू काम बिगाड़कर यह जताता है कि वह इन कार्यों में सक्षम ही नहीं है। नीतजीतन पत्नी को ही दोबारा सब कुछ करना पड़ता है और धीरे-धीरे घर का पूरा बोझ उसी के कंधों पर आ जाता है।

कल्पना कीजिए कि पत्नी कहती है कि रसोई में सब्जी बनाओ। पति नमक इतना डाल देगा कि खाना खाने लायक ही न रहे। या फिर कपड़े धोते समय वह रंगीन और सफेद कपड़े एक साथ डाल देगा ताकि वे खराब हो जाएँ। बच्चे को होमवर्क कराने की जिम्मेदारी मिले तो वह आधे मन से बैठकर बच्चा और उलझा दे। ऐसे मामलों में वह बाद में सहजता से कह देता है – देखो, मुझसे नहीं होता, तुम ही कर लो। इस तरह बार-बार की गई ऐसी घटनाएँ पत्नी को मजबूर कर देती हैं कि वह सब कुछ स्वयं संभाले। यह प्रवृत्ति केवल गलतफहमी का रूप नहीं है, बल्कि मानसिकता की गहराई में छिपा हुआ लैंगिक भेदभाव है। समाज ने सदियों से यह धारणा बना दी है कि घरेलू काम महिलाओं का दायित्व है और पुरुष केवल बाहर की जिम्मेदारियों तक सीमित हैं। लेकिन आज के समय में जब महिलाएँ बाहर भी बराबरी की जिम्मेदारी उठा रही हैं, तब यह तर्क न तो न्यायसंगत है और न ही स्वीकार्य।

प्रेरक प्रसंग

मातृमक्ति से राष्ट्रमक्ति

तमिलनाडु के विरुधुनगर में 15 जुलाई, 1903 को कामाक्षी कुमारस्वामी नादेर नामक एक बालक का जन्म हुआ। उसने 4 वर्ष की आयु में पारंपरिक स्कूल में जाना प्रारम्भ कर दिया था। छह वर्ष की अल्पायु में इनके पिता का देहावसान हो गया। पिता की मृत्योपरांत घर के कामकाज और खर्च का बोझ इनकी माँ पर आन पड़ा। माता की यह दयनीय स्थिति देख, बालक कामाक्षी कुमारस्वामी ने मां को घर के काम में सहायता हेतु अपनी पढ़ाई छोड़ दी। थोड़ा बड़ा हुआ तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा चलाये जा रहे होम रूल आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। भारत की आजादी हेतु पूर्णकालिक राजनीतिक कार्यकर्ता के साथ-साथ 1946 में कामाक्षी कुमारस्वामी भारत के संविधान सभा के लिए चुने गए। लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में अहम योगदान देने वाला मातृभक्त और राष्ट्रभक्त बालक यह कामाक्षी कुमारस्वामी ही नादेर के कामराज थे। जिनके नाम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी बनी थी। देश सेवा के जज्बे में इनका कम पढ़ा-लिखा होना कभी आड़े नहीं आया।

सामयिक



भारत में अब ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्मार्ट ग्रिड, बैटरी स्टोरेज और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसे कदम भी तेजी से आगे बढ़ाए जा रहे हैं, जो अक्षय ऊर्जा को व्यावहारिक और टिकाऊ बनाएंगे। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत वर्ष 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिससे भारत न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि निर्यातक देश भी बन सकेगा। सही मायने में अक्षय ऊर्जा ही आज भारत में विभिन्न रूपों में ऊर्जा की जरूरतों का प्रमुख विकल्प है, जो पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ टिकाऊ भी है।

देश के सतत विकास की धुरी है अक्षय ऊर्जा

योगेश कुमार गोयत

मोबाइल : 9416740584.

पृथ्वी पर ऊर्जा के परम्परागत साधन बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, ऐसे में खतरा मंडरा रहा है कि यदि ऊर्जा के इन पारम्परिक स्रोतों का इसी प्रकार दोहन किया जाता रहा तो इन परम्परागत स्रोतों के समाप्त होने पर गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। यही कारण है कि पूरी दुनिया में गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने की जरूरत महसूस की जाने लगी और इसी कारण अक्षय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति करने के प्रयास शुरू हुए। अक्षय का अर्थ है, जिसका कभी क्षय न हो अर्थात अक्षय ऊर्जा वास्तव में ऊर्जा का असीम और अनंत विकल्प है और आज के समय में यह किसी भी राष्ट्र के अक्षय विकास का प्रमुख स्तंभ भी है। पिछले कुछ वर्षों से पर्यावरणीय चिंताओं को देखते हुए ऐसी ऊर्जा तथा तकनीकें विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिनसे ग्लोबल वार्मिंग की विकराल होती समस्या से दुनिया को कुछ राहत मिल सके। किसी भी राष्ट्र को विकसित बनाने के लिए आज प्रदूषणरहित अक्षय ऊर्जा स्रोतों का समुचित उपयोग किए जाने की आवश्यकता भी है। देश में अक्षय ऊर्जा के विकास और उपयोग को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए ही वर्ष 2004 से हर साल 20 अगस्त को 'अक्षय ऊर्जा दिवस' भी मनाया जाता है।

आज न केवल भारत में बल्कि समूची दुनिया के समक्ष बिजली जैसी ऊर्जा की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए सीमित प्राकृतिक संसाधनों हैं, साथ ही पर्यावरण असंतुलन और विस्थापन जैसी भीषण चुनौतियां भी हैं। चर्चित पुस्तक 'प्रदूषण मुक्त सांस' के अनुसार इन गंभीर समस्याओं और चुनौतियों से निपटने के लिए अक्षय ऊर्जा ही एक ऐसा बेहतरीन विकल्प है, जो पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के साथ-साथ ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने में भी कारगर साबित होगी लेकिन अक्षय ऊर्जा की राह में भी कई चुनौतियां मुंह बाये सामने खड़ी हैं। अक्षय ऊर्जा उत्पादन की देशभर में कई छोटी-छोटी इकाइयां हैं, जिन्हें एक ग्रिड में लाना बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य है। इससे बिजली की गुणवत्ता प्रभावित होती है। भारत में अक्षय ऊर्जा के विविध स्रोतों का अपार भंडार मौजूद है लेकिन इनसे ऊर्जा उत्पादन करने वाले अधिकांश उपकरण विदेशों से आयात किए जाते हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के अनुसार, कुछ साल पहले सौर ऊर्जा के लिए करीब 90 प्रतिशत उपकरण विदेशों से आयात किए गए थे, जिससे बिजली उत्पादन की लागत काफी बढ़ गई। 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार, अब भी भारत की सौर सेल और मॉड्यूल की जरूरत का अधिकांश हिस्सा, कभी-कभी 90 प्रतिशत तक, आयात से ही पूरा होता रहा है। हालांकि हाल के वर्षों में एएलएमएम नियम और पीएलआई स्कीम के कारण यह निर्भरता घट रही है। 2023-24 में चीन से सौर सेल्स का 53 प्रतिशत और मॉड्यूल्स का 63 प्रतिशत भारत में आया।

देश में ऊर्जा की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर भी तेजी से बढ़ रहा है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के आंकड़ों के अनुसार देश में कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 450 गीगावॉट से अधिक हो चुकी है, जिसमें अब 230 गीगावॉट से अधिक अक्षय ऊर्जा से प्राप्त हो रहा है, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायो-पावर और छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अधिक बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं से तथा परमाणु ऊर्जा से भी अक्षय ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। कुल बिजली उत्पादन में अब अक्षय ऊर्जा का हिस्सा अब लगातार बढ़ रहा है, जो भारत को दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल करता है।

भारत में ऊर्जा खपत भी तेजी से बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) का अनुमान है कि वर्ष 2040 तक भारत में ऊर्जा की कुल मांग वर्तमान की तुलना में लगभग दोगुनी हो जाएगी। विशेषकर बिजली तथा ईंधन के रूप में उपभोग की जा रही ऊर्जा की मांग घरेलू एवं कृषि क्षेत्र के अलावा औद्योगिक क्षेत्रों में भी लगातार बढ़ रही है। औद्योगिक क्षेत्रों में ही बिजली तथा पेट्रोलियम जैसे ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोतों का लगभग 55 प्रतिशत उपभोग किया जाता है। हम जिस बिजली से अपने घरों, दुकानों या दफ्तरों को रोशन करते हैं, जिस बिजली या पेट्रोलियम इत्यादि ऊर्जा के अन्य स्रोतों का इस्तेमाल कर खेती-बाड़ी या उद्योग-धंधों के जरिये देश को विकास के पथ पर अग्रसर किया जाता है, क्या हमने कभी सोचा है कि वह बिजली या ऊर्जा के अन्य स्रोत हमें कितनी बड़ी कीमत पर हासिल होते हैं? यह कीमत न केवल आर्थिक रूप से बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी धरती पर विद्यमान हर प्राणी पर बहुत भारी पड़ती है। भारत में थर्मल पावर स्टेशनों में बिजली पैदा करने के लिए प्रतिदिन लगभग 18 लाख टन कोयले की खपत होती है। आज भी देश की लगभग 55 प्रतिशत से अधिक बिजली कोयले से ही पैदा होती है, शेष बिजली अक्षय ऊर्जा स्रोतों, जल, गैस व परमाणु ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होती है।

दुनियाभर में ऊर्जा क्षेत्र में लगभग 75 प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन बिजली उत्पादन से ही होता है। यही कारण है कि अब सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों को विशेष महत्व दिया जाने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, यदि

अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता पर विशेष ध्यान दिया जाए तो वर्ष 2050 तक वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को 70 प्रतिशत तक घटाया जा सकता है। भारत ने भी 2030 तक 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता हासिल करने और नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य वर्ष 2070 तक प्राप्त करने का संकल्प लिया है। अक्षय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देने से हमारी ऊर्जा की मांग और आपूर्ति के बीच का अंतर कम होता जाएगा और इससे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक जीवन स्तर में भी सुधार होगा।

भारत में अब ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्मार्ट ग्रिड, बैटरी स्टोरेज और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसे कदम भी तेजी से आगे बढ़ाए जा रहे हैं, जो अक्षय ऊर्जा को व्यावहारिक और टिकाऊ बनाएंगे। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत वर्ष 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिससे भारत न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि निर्यातक देश भी बन सकेगा। सही मायने में अक्षय ऊर्जा ही आज भारत में विभिन्न रूपों में ऊर्जा की जरूरतों का प्रमुख विकल्प है, जो पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ टिकाऊ भी है।

भारत धीरे-धीरे ही सही, अब इस दिशा में आगे बढ़ रहा है और आज समय है कि हम आर्थिक बढ़हाली और भारी पर्यावरणीय विनाश की कीमत पर ताप, जल एवं परमाणु ऊर्जा जैसे पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर रहने के बजाय अपेक्षाकृत बेहद सस्ते और कार्बन रहित पर्यावरण हितैषी ऊर्जा स्रोतों के व्यापक स्तर पर विकास के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ें। साथ ही हमें ऊर्जा की बचत की आदतें भी अपनानी होंगी क्योंकि ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग ही हमें सुरक्षित, समृद्ध और स्वच्छ भविष्य की ओर ले जाएगा।

नजरिया

साझेदारी और बराबरी से ही टिकेगा आधुनिक विवाह



कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान यह स्थिति और स्पष्ट होकर सामने आई। जब दफ्तर घरों में सिमट गए, बच्चे पूरे समय घर में रहने लगे और बाहर से सहायक मिलना बंद हो गया, तब लाखों परिवारों में यह देखा गया कि महिलाओं पर काम का बोझ कई गुना बढ़ गया। वे दिनभर ऑनलाइन मीटिंग्स में भी थीं और साथ ही तीन वक्त का खाना बनाने, बच्चों को पढ़ाने, सफाई करने और बुजुर्गों की देखभाल करने की जिम्मेदारी भी निभा रही थीं। पति जहाँ तक संभव हुआ, इन जिम्मेदारियों से बचते रहे और बहाना यही रहा कि वे घर के कामों में उतने माहिर नहीं हैं। इस परिस्थिति ने कई रिश्तों में तनाव को जन्म दिया और कई परिवारों में तलाक और अलगाव की घटनाएँ बढ़ीं। महिलाएँ अब पहले जैसी स्थिति में चुपचाप समझौता नहीं कर रही हैं। शिक्षित और आत्मनिर्भर होने के कारण वे बराबरी की मांग कर रही हैं। उनके लिए विवाह अब केवल परंपरा निभाने का नाम नहीं है, बल्कि एक साझेदारी है। इस साझेदारी का अर्थ है कि दोनों साथी मिलकर घर की जिम्मेदारियाँ बाँटें। जब पति जानबूझकर अयोग्यता दिखाता है तो यह सीधे-सीधे पत्नी के आत्मसम्मान और मानसिक स्वास्थ्य पर चोट करता है। कई बार यह स्थिति डिप्रेशन, चिंता और थकान का कारण बन जाती है।मनोवैज्ञानिक

दृष्टिकोण से भी यह प्रवृत्ति रिश्तों को नुकसान पहुँचाती है। रिश्ता तभी मजबूत होता है जब उसमें बराबरी और विश्वास का भाव हो। यदि एक पक्ष बार-बार जिम्मेदारी से भागे और दूसरा पक्ष मजबूरी में सब कुछ ढोता रहे तो धीरे-धीरे नाराजगी, कड़वाहट और दूरी बढ़ जाती है। पत्नी को लगता है कि उसकी मेहनत को महत्व नहीं दिया जा रहा और पति को लगता है कि वह अपनी सुविधा से बच निकला है। यह असंतुलन लंबे समय तक नहीं चल सकता। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस विषय पर शोध हुए हैं। अमेरिका, कनाडा और यूरोप के कई समाजशास्त्रीय अध्ययनों में पाया गया है कि घरेलू कार्यों का असमान वितरण तलाक का एक बड़ा कारण है। भारत में भी यही प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। बदलते शहरी जीवन, दोहरे रोजगार और छोटे परिवारों की पृष्ठभूमि में महिलाएँ अधिक मुखर हो रही हैं और बराबरी की मांग खुलकर रख रही हैं। इस समस्या का समाधान केवल कानून या सामाजिक दबाव से नहीं निकलेगा, बल्कि यह पति-पत्नी के आपसी संवाद और समझदारी से ही संभव है। पुरुषों को यह समझना होगा कि घरेलू कार्य केवल साधारण काम नहीं हैं, बल्कि वे परिवार की नींव को मजबूत रखते हैं। यदि रसोई का काम, बच्चों की पढ़ाई या घर की सफाई समय पर और ठीक से न हो तो घर का

वातावरण बिगड़ जाता है और तनाव बढ़ता है। इसलिए इन्हें हल्के में लेना या केवल महिला पर थोपना उचित नहीं। इसी तरह महिलाओं को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि वे बिना कहे हर जिम्मेदारी अपने ऊपर न लें। कई बार महिलाएँ यह सोचकर चुप रह जाती हैं कि वह नहीं करेगा तो मुझे ही करना होगा। धीरे-धीरे यह पैटर्न स्थायी हो जाता है और पति जिम्मेदारी से बचने का आदी बन जाता है। इसलिए आवश्यक है कि शुरुआत से ही दोनों के बीच काम बाँटने की आदत विकसित हो। शिक्षा प्रणाली और सामाजिक अभियानों में भी यह संदेश देना होगा कि घरेलू कार्य किसी एक लिंग की जिम्मेदारी नहीं हैं। बच्चों को बचपन से ही यह सिखाना होगा कि लड़का और लड़की दोनों बर्तन धो सकते हैं, खाना बना सकते हैं और घर का हर काम कर सकते हैं। जब यह सोच बचपन से पनपेगी तभी आने वाली पीढ़ी में असमानता घटेगी। समाज को यह भी स्वीकार करना होगा कि घरेलू कार्यों की भी आर्थिक और सामाजिक कीमत है। यदि कोई महिला या पुरुष दिनभर घर के काम कर रहा है तो वह भी उतनी ही मेहनत कर रहा है जितना कोई नौकरी करने वाला। इसे केवल महिला का काम कहकर कमतर आँकना अन्यायपूर्ण है।

पति द्वारा घरेलू कार्यों में अयोग्यता दिखाना केवल व्यक्तिगत रिश्तों को नहीं तोड़ता, बल्कि यह समाज में असमानता और अन्याय को भी गहरा करता है। यदि आधुनिक विवाह को टिकाऊ और मजबूत बनाना है तो यह मानसिकता बदलनी ही होगी। साझेदारी और बराबरी ही आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत हैं। अंततः यही कहा जा सकता है कि विवाह केवल साथ रहने का अनुबंध नहीं है। यह एक ऐसा बंधन है जिसमें दोनों साथी मिलकर एक-दूसरे की खुशियों और कठिनाइयों को साझा करते हैं। यदि पति जिम्मेदारियों से बचने के लिए अयोग्यता का बहाना बनाएगा तो यह रिश्ते को खोखला कर देगा। इसके विपरीत यदि वह बराबरी से जिम्मेदारी उठाएगा तो न केवल रिश्ते में विश्वास और प्रेम बढ़ेगा, बल्कि परिवार भी खुशहाल और सफल बनेगा। इसलिए अब समय आ गया है कि समाज इस प्रवृत्ति को सामान्य मानने के बजाय इसे चुनौती दे। महिलाएँ बराबरी की हकदार हैं और पुरुषों को बराबरी से जिम्मेदारी निभानी होगी। तभी आधुनिक विवाह वास्तव में सफल और टिकाऊ बन पाएगा।

